



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28052020-219622
CG-DL-E-28052020-219622

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1495]
No. 1495]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2020/ज्येष्ठ 6, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2020/JYAISHTHA 6, 1942

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2020

का.आ. 1662(अ).—केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित में भू-मार्ग या जल मार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए परिवहन सेवाएं (रेल से भिन्न), जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 1 के अधीन आती हैं, को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित किया जाना चाहिए ;

और केन्द्रीय सरकार ने अंतिम बार उक्त उद्योग को भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3374 (अ), तारीख 19 सितम्बर, 2019 द्वारा अंतिम रूप से तारीख 19 सितम्बर, 2019 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा के रूप में घोषित किया है;

और केन्द्रीय सरकार का यह राय है कि छह मास की और अवधि के लिए उक्त उद्योग की लोकहित उपयोगिता सेवा प्रास्थिति का विस्तार करना लोकहित में अपेक्षित है ;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भू-मार्ग या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या मालों के वहन के लिए (रेल से भिन्न) में उक्त सेवाओं को छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगिता सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस-11017/1/2009-आईआर(पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th May, 2020

S.O. 1662(E).—Whereas, the Central Government is satisfied that public interest requires that the services in the Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water, which is covered under item 1 of the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purposes of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 19th September, 2019 vide notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 3374 (E), dated the 19th September, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government, hereby declares from the date of publication of this notification the said services in the Transport (other than railways) for the carriage of passengers or goods, by land or water, to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[F. No. S-11017/1/2009-IR(PL)]

KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.